of Government will be formulated keeping these views along with such others which are available with the Government.

Industrial Projects in Karnataka during Fifth Plan

4096. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the industrial projects in the first year of the Fifth Five Year Plan which are proposed to be undertaken by the Central Government in the State of Karnataka; and

(b) the allotment of funds made to Karnataka Government for the development of industries during the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) The names of Central industrial and mineral projects to be undertaken during the Fifth Plan in the various States, including Karnataka, alongwith their locations and outlays (to the extent decisions have been taken) are indicated at pages 151—155 (Vol. II) of the Draft Fifth Plan Document. During the first year of the Fifth Plan, the central industrial projects to be taken up in Karnataka relate to:—

(i) Bharat Gold Mines.

(ii) Mandya Unit of Hindustan Paper Corporation.

(iii) Hindustan Machine Tools.

(iv) Plantation Industry.

(b) During the Fifth Plan, an outlay of Rs. 29 crores has been tentatively agreed upon towards the ies' Fifth Five Year Plan for Large & Medium Industries (Rs. 18 crores), Mineral Development (Rs. 1 crore) and Village & Small Industries (Rs. 10 crores).

Establishment of a Mizoram Peace Mission

4097. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have seen the press reports of establishment of a Mizoram Peace Mission in the Union territory of Mizoram with a view to bringing the rebels and the Government of India to the Round Table Conference;

(b) whether Government would explore the possibility of finding out a durable and peaceful solution of the Mizo problem within the framework of the Indian Constitution; and

(c) whether Government will take the assistance of such bodies like Mizoram Peace Mission and associate prominent individuals of proven integrity for finding out a peaceful solution?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Government have seen the press reports in question.

(b) and (c) Efforts to bring back the Mizo rabels to peaceful democratic life within the Constitution cannot be meaningful so long as the Mizo rebels continue their treasonable activities.

मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा धनराशि की स्वीकृति

4098. श्री भागीरथ भंवर: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार विभिन्न परियोजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में कार्यक्रम और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम हुआ था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों में स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	ऋण की राशि		
	सामान्य ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	जोड़
		(करोड़ रुपये)	
1971–72	5.23	0.05	5.28
1972–73	9.94	0.14	10.08
1973–74	9.08	0.31	9.39
जोड़	24.25	0.50	24.75

(ख) और (ग) निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं इन पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरण-बद्ध की जाती हैं। 1971-72 और 1972-73 में स्वीकृति एरियों के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रम और लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। बहरहाल, समितियों की अधिप्राप्ति में पेश आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, प्रगति संतोषजन की समझी जाती है ।

1973–74 में स्वीकृत हुई स्कीमों पर अभी हाल में कार्य प्रारम्भ हुआ है और उनके संबंध में हुई प्रगति का अभी मूल्यांकन किया जाना है ।

जिला स्तर पर योजना विकास समितियां

4099. श्री भागीरथ भंवर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को निदेश दिये हैं कि जिला स्तर पर योजना विकास समितियां बनाई जायें और निर्वाचित सदस्य उससे सम्बद्ध किये जायें;

(ख) किन-किन राज्य ने इन निदेशों का पालन किया है; और

(ग) शेष राज्य उनका कब तक पालन करेंगे ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : (क) योजना आयोग ने जिला स्तर पर आयोजन संगठन गठित करने के महत्व पर बल दिया है और इन संगठनों में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की आवश्यकता का महत्व भी बताया है।

(ख) निम्नांकित राज्यों ने जिला (उप-विभागीय) स्तर पर आयोजन संगठन गठित कर दिये हैं तथा उनमें संसद सदस्य/विधायक भी हैं : असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ग) स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने के लिए समुचित संरचना की स्थापना करने का काम राज्य सरकारों का है। देश भर में अनुसरण के लिए न समान प्रणाली निर्धारित करना सम्भव है और न ही यह बताना सम्भव है कि बाकी राज्य कब तक जिला स्तर पर आयोजन संगठनों का गठन कर लेंगे।